एमएसएमई के लिए 480 करोड़

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के लिए बजट में 480 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके लिए एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत दिए जाने वाले प्रोत्साहन को अगले वित्त वर्ष में भी जारी रखने का एलान किया गया है।

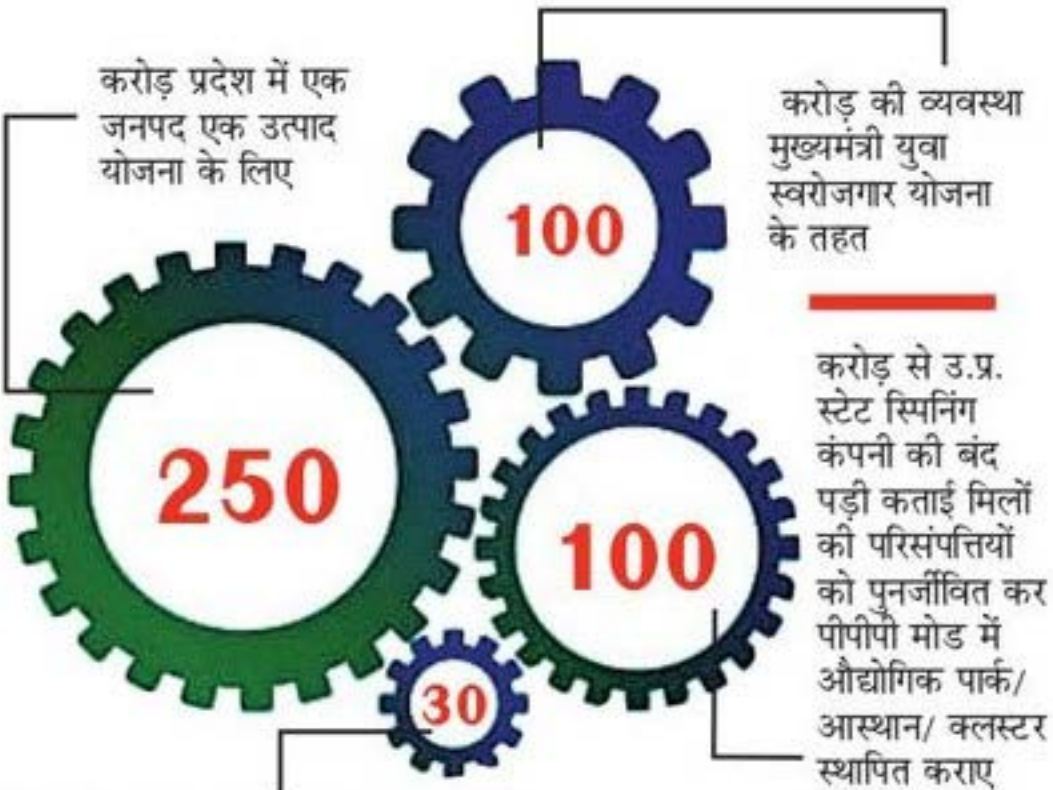

विधायकों की सिफारिश पर विकास कार्यों के लिए पैसा

1512 करोड़ का प्रावधान

विधायक एक बार फिर अपने क्षेत्र के विकास के लिए संस्तुति कर सकेंगे। इसके लिए बजट में 1512 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कोरोना काल के उपरांत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के विकास में विधानमंडल सदस्यों के प्रत्यक्ष योगदान के लिए उनके क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए उनकी संस्तुति पर विकास निधि के बराबर राशि उपलब्ध कराई जाएगी।